जनपद का एक लोक प्रिय हिन्दी समाचार पत्र– RNI.No.UPHIN/2013/54086
Mob-9307000600

मिशन विजय

(साप्ताहिक)

मिशन विजय
व्यवसायिक विज्ञापन दरें
पूर्ण पृष्ठ– 12000 रूपया
आधा पृष्ठ– 6000 रूपया
चौथाई पृष्ठ– 3000 रूपया
45 रूपया प्रति कालम प्रति से0मी

वर्ष : 09 | अंक 15 | सुलतानपुर, मंगलवार 19 जनवरी 2020 | पृष्ट : 04 | मूल्य 1 रूपया

सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश– तीन सप्ताह में लग जाए सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन

लखनऊ संवाददाता। कोरोना टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि पहले चरण के तहत अगले तीन सप्ताह में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगा दी जाए। इसके साथ ही दूसरे चरण की सभी तैयारियां समय से पूरी कर लें। सीएम योगी ने एक बार फिर आगाह किया है कि वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना संक्रमण के प्रति सतर्कता बरतनी होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन में टीम 11 के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का काम सप्ताह में दो दिन गुरुवार और शुक्रवार को किया जाना है। पहले चरण के तहत अगले तीन सप्ताह में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लग जाए। 15 फरवरी, 2021 से पहले चरण वालों को वैक्सीन की दूसरी डोज देना शुरू कर दें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड–19 के प्रसार को रोकने में जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रतिदिन कम से कम 1.50 लाख जांच अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा आरोग्य मेलों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इन मेलों में आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की जानकारी लोगों को दी जाए। पात्र लाभार्थियों को इन योजनाओं के गोल्डन कार्ड भी वितरित करें। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल आदि उपस्थित थे।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना टीकाकरण की पहली डोज से बचे स्वास्थ्य कर्मियों को 22 जनवरी को टीके लगाए जाएंगे। इसके बाद हफ्ते में दो दिन टीके लगाए जाएंगे। शनिवार को कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के मौके पर प्रदेश में 22,643 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई थी। प्रदेश में कुल 317 स्थानों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। वैक्सीन की दूसरी डोज 15 फरवरी को लगाई जाएगी। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाये जाने हैं, उनकी सूची बनायी जा रही है और कोविन पोर्टल पर उनकी रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। जिन्हें टीके लगने हैं, कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होते ही उनके पास एसएमएस जाएगा जिसके जरिये उन्हें जानकारी दी जाएगी कि उन्हें कब, कहां और कितने बजे टीका लगना है।

कमल हासन के पैर की होगी सर्जरी, बोले– जल्द ही चुनाव अभियान को फिर से शुरू करने के लिए वापस आऊंगा

चेन्नई सं0। मक्कल निधि मैयम (एमएनएम) प्रमुख कमल हासन ने रविवार को कहा कि वह अपने पैर की एक अनुवर्ती सर्जरी कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि वह अपने चुनाव अभियान को फिर से शुरू करने के लिए जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस आएंगे। हासन ने कहा कि कुछ साल पहले हुई एक दुर्घटना के कारण उनके पैर की सर्जरी हुई थी और उनके लिए एक अनुवर्ती सर्जरी कराना आवश्यक है। उन्होंने एक बयान में कहा कि चिकित्सकों द्वारा उन्हें अनुवर्ती सर्जरी पूरी होने तक आराम करने की सलाह दिए जाने के बावजूद उन्होंने अपने पेशेवर और राजनीतिक कार्य जारी रखे।

हासन ने कहा, "तमिलनाडु के लोगों के प्यार और स्नेह ने उस गंभीर दर्द के लिए एक प्रभावी मारक का काम किया जो मैं अपने अभियान के दौरान झेलता था। अब मुझे कुछ आराम करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं सलाह के अनुसार अपने पैर की एक अनुवर्ती सर्जरी कराऊंगा। मैं कुछ दिनों बाद नए जोश से अपने अभियान को फिर से शुरू करने के लिए वापस आऊंगा।" तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव अप्रैल, मई 2021 में होने की संभावना है।

नौकरशाहों का राजनीति में आना पार्टियों के लिए इतना जरूरी क्यों?

जब से गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा ने वीआरएस लेकर राजनीति में प्रवेश किया है, इस बात को लेकर चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि राजनीति में नौकरशाहों की सीधी एंट्री पर आखिर इतनी चुप्पी क्यों है? क्यों सभी सरकारे नौकरशाहों के लिए राजनीतिक एंट्री के दरवाजे सीधे–सीधे खुला रखना चाहते हैं? आखिर सभी दल इस मसले को लेकर इतने शांत क्यों रहते हैं? इस बात को भी लेकर भी बहस है कि वीआरएस लेकर नौकरशाहों या फिर दूसरे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का राजनीति में आना संस्था की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाते हैं? अरविंद कुमार शर्मा को लेकर इस बात की चर्चा तेज है कि उन्हें आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि यह चर्चा पहली बार नहीं हो रही है। बिहार चुनाव से पहले जब गुप्तेश्वर पांडे ने भी वीआरएस लिया था तब भी इस तरीके की चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि यह चर्चा कभी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। चुनाव बाद सब कुछ शांति हो जाता है।

यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि हमने कई मौकों पर देखा है कि नौकरशाह, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति तत्काल राजनीति में आ जाते हैं। हालांकि संविधान में इसको लेकर किसी बात पर रोक तो नहीं लगाई गई है लेकिन कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं पर इससे सवाल जरूर उठने लगते हैं और उसकी विश्वसनीयता में कमी आती है। सालों में हमने देखा है कि यह एक परंपरा सी बन गई है जब राज्य, केंद्र के चुनाव से पहले संवैधानिक संस्थाओं में बैठे व्यक्ति या फिर नौकरशाह वीआरएस लेकर राजनीति में एंट्री मारने को इच्छुक हो जाते हैं। पर इसके बाद उन पर इस बात को लेकर आरोप लगने लगते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए की खास दल से नजदीकी रखी है। इस वजह से उनकी निष्ठा भी सवाल उठने लगते हैं।

रिटायरमेंट या फिर वीआरएस लेकर तुरंत चुनाव में उतरने पर राजनीतिक दल पहले तो विरोध करते थे। लेकिन आजकल उनकी चुप्पी शायद इस बात की इजाजत दे रही है। तभी तो इस तरीके की स्थिति सभी पार्टियों में होती है। हालांकि, चुनाव आयोग ने इस परंपरा को गलत माना है। आयोग ने तो यह तक सिफारिश कर दी है कि वीआरएस, रिटायरमेंट लेने के कम से कम 2 साल बाद ही कोई राजनीति में आए। लेकिन चुनाव आयोग की इस सिफारिश को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर राजनीतिक दल इस पर रोक लगाने को तैयार क्यों नहीं होते? दरअसल, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आम जनता तक अपने काम को पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका पार्टियों के पास नौकरशाही ही होते हैं। नौकरशाह के जरिए ही वह अपनी स्थिति को जमीन पर मजबूत कर पाती हैं। ऐसे में कई नौकरशाहों के साथ उनके संबंध स्थापित हो जाते हैं और यही कारण है कि फिर उन्हें पार्टी में लेना उनके लिए मजबूरी थी बन जाती है।

गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, योगेंद्र यादव बोले– परेड में नहीं होगा कोई व्यवधान

नयी दिल्ली सं0। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं किसान यूनियनों ने रविवार को कहा कि वे गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड निकालेंगी। यूनियन नेता योगेंद्र यादव ने सिंघू बार्डर स्थित प्रदर्शन स्थल पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर एक ट्रैक्टर परेड करेंगे। परेड बहुत शांतिपूर्ण होगी। गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। किसान अपने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे।"

प्राधिकारियों ने किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च या ऐसे किसी अन्य प्रकार के विरोध प्रदर्शन पर रोक की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है ताकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में किसी तरह की बाधा न आये। उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका पर 18 जनवरी को सुनवायी किये जाने की संभावना है। एक अन्य किसान यूनियन नेता दर्शन पाल सिंह ने आरोप लगाया कि एनआईए उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है जो विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं या इसका समर्थन कर रहे हैं। पाल ने कहा, "सभी किसान यूनियन इसकी निंदा करती हैं।"

पाल का इशारा एनआईए के उन समन की ओर था जो प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' से जुड़े एक मामले में एक किसान यूनियन नेता को कथित तौर पर जारी किये गए हैं। सरकार और प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के बीच 10वें दौर की वार्ता 19 जनवरी को होनी निर्धारित है। गतिरोध को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति भी उसी दिन अपनी पहली बैठक करेगी। केंद्र और 41 किसान यूनियनों के बीच पिछले नौ दौर की औपचारिक वार्ता से दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है क्योंकि किसान यूनियन तीनों कानूनों को पूरी तरह से निरस्त करने की अपनी मुख्य मांग पर अड़े हुए हैं।

उच्चतम न्यायालय ने गत 11 जनवरी को अगले आदेश तक तीन कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी और गतिरोध के समाधान के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया था। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान ने पिछले सप्ताह खुद को समिति से अलग कर लिया था। शेतकारी संगठन (महाराष्ट्र) के अध्यक्ष अनिल के अलावा, कृषि अर्थशास्त्रियों अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी अन्य समिति के अन्य सदस्य हैं। घनवट ने शनिवार को पीटीआई–से कहा, "हम 19 जनवरी को पूसा परिसर में बैठक कर रहे हैं। आगे के कदम पर निर्णय करने के लिए केवल सदस्य ही बैठक करेंगे।"

संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा, "परेड में वाहनों पर झांकियां शामिल होंगी जो ऐतिहासिक क्षेत्रीय और अन्य आंदोलनों प्रदर्शित करने के अलावा विभिन्न राज्यों की कृषि वास्तविकता को दर्शाएंगी।" उसने कहा, "वाहनों पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा होगा और साथ ही उन पर उस किसान संगठन का झंडा भी होगा, जिससे उक्त सदस्य संबद्ध है। किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली के विभिन्न बार्डर पर एक महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इन कानूनों को किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमुख कृषि सुधारों के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान चिंता जता रहे हैं कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और "मंडी" व्यवस्था को कमजोर करेंगे उन्हें बड़े कॉरपोरेट की दया पर छोड़ देंगे। सरकार का कहना है कि ये आशंकाएं गलत हैं। सरकार कानूनों को निरस्त करने से इनकार कर चुकी है।

सम्पादकीय–

टीआरपी घोटाले की रेंज

मुंबई पुलिस द्वारा उजागर किया गया टीआरपी घोटाला शुरू में सीमित महत्व का ही माना जा रहा था, लेकिन ब्यौरे उजागर होने के साथ यह विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। बीते सप्ताह मुंबई पुलिस की ओर से फाइल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बतौर सबूत शामिल किए गए वॉट्सऐप चौट सामने आने से इस प्रकरण के साजिश वाले पहलू अचानक बेहद गंभीर हो गए। हालांकि अभी इस मामले में जांच चल ही रही है। पुलिस द्वारा जुटाए गए तमाम सबूतों का अदालत में परीक्षण होना बाकी है लेकिन जो साक्ष्य अब तक सामने आए हैं वे इतना तो बताते ही हैं कि इस मामले को महज बीएआरसी (ब्रॉडकास्ट ऑडिएंस रिसर्च काउंसिल) के स्तर पर होने वाली गड़बड़ी के रूप में नहीं समझा जा सकता।

साफ लगता है कि एक खास चौनल की तरफ से उसको फायदा पहुंचाने के लिए बीएआरसी में अहम पदों पर बैठे कुछ लोगों का इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, इसमें अति संवेदनशील मुद्दे पर अग्रिम जानकारी साझा की गई है, जो स्वयं में एक स्वतंत्र जांच का मुद्दा होना चाहिए। कोई चौनल या पत्रकार खुद को नंबर वन दिखाने के लिए सत्ता में अपनी पहुंच का कैसा इस्तेमाल कर सकता है, यह तो इससे साफ होता ही है, साथ ही यह सवाल भी उठने लगता है कि सत्ता में अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए वह खबरों के साथ कैसा खिलवाड़ करता होगा। पत्रकार और मीडिया के साथ प्रामाणिकता की जो शर्त जुड़ी हुई है, उसकी अगर एक मामले में धज्जियां उड़ाते आप दिख जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके सारे काम संदेह के घेरे में आ जाते हैं।

ये वॉट्सऐप चैट अगर सही हैं तो कहना ही होगा कि मामले का मुख्य आरोपी या कथित मास्टरमाइंड बीएआरसी में बैठा शख्स नहीं बल्कि चौनल के ऑफिस से उसे निर्देशित करने वाला व्यक्ति है। बीएआरसी के संबंधित अधिकारी पर अधिक से अधिक अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए पद के दुरुपयोग का मामला बनता है, लेकिन चौनल संचालकों पर न केवल विज्ञापनदाताओं के साथ बेईमानी और बाकी चौनलों के साथ धोखाधड़ी करने का बल्कि दर्शकों के साथ विश्वासघात करने का भी आरोप चस्पां होता है। इसके अलावा सत्ता से नजदीकी के गलत इस्तेमाल का सवाल अपनी जगह है।

इस चौनल की रिपोर्टिंग को लेकर जितनी शिकायतें की जाती रही हैं, ताजा प्रकरण के बाद क्या उन सबको पत्रकारीय विवेक की स्वतंत्रता का हवाला देकर दरकिनार किया जा सकेगा? बात जहां तक कानूनी प्रक्रिया की है तो उसे अपने तय रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी देखा जाना चाहिए कि इस रास्ते में किसी तरह की रुकावट न आए और किसी संदेह या अविश्वास के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए। मीडिया के आत्म अनुशासन का रास्ता भी ऐसे विचलनों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए ही तैयार हो पाएगा, इनकी अनदेखी करके नहीं।

रक्षा में आत्मनिर्भरता

वायुसेना के लिए 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को सरकार द्वारा दी गई मंजूरी मौजूदा हालात में कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। देश के अंदर निर्मित तेजस विमान खरीदने का यह 48,000 करोड़ रुपये का सौदा घरेलू रक्षा उद्योग के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। देश के अंदर रक्षा खरीद का यह अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ठीक ही उम्मीद जताई है कि तेजस कार्यक्रम भारत के एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ध्यान रहे कि इस ऑर्डर को पूरा करने के क्रम में डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी देश की करीब 500 छोटी–बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (हाल) के साथ मिलकर काम करेंगी। स्वाभाविक रूप से यह फैसला इन क्षेत्रों को नए जोश से भर सकता है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ने में भी इससे मदद मिलेगी। हालांकि इस विमान को बनाने में हमारी प्रगति कितनी धीमी रही है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि देश के अंदर लड़ाकू विमान बनाने का यह प्रॉजेक्ट 50 साल से ज्यादा पुराना है। पहली बार 1969 में सरकार ने एयरोनॉटिक्स कमिटी की यह सिफारिश मंजूर की थी कि 'हाल' को देश में ही लड़ाकू विमान बनाने चाहिए। इसके बाद अलग–अलग कारणों और प्राथमिकताओं के चलते इस प्रॉजेक्ट पर काम चींटी जैसी रफ्तार से ही आगे बढ़ा। अस्सी के दशक में जब वायु सेना को यह महसूस हुआ कि मिग–21 पुराने पड़ते जा रहे हैं और इनकी जगह भारतीय लड़ाकू विमानों की जरूरत उसे पड़ने वाली है, तब जरूर तेजस प्रॉजेक्ट में कुछ तेजी आई।

खास बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर सचमुच गंभीर हुई है और उसने कई ऐसे फैसले किए हैं जिनसे इस दिशा में आगे बढना आसान हुआ है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल मई में देश के अंदर बने मिलिट्री हार्डवेयर की खरीद के लिए अलग से बजट प्रावधान करने की घोषणा की थी। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा भी 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दी गई थी। इसके अलावा ऐसे हथियारों की सालाना सूची जारी की गई जिनका आयात नहीं किया जाएगा।

इन कदमों की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि सरकार ने साल 2025 तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का टर्नओवर 1.75 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है। जाहिर है, रक्षा में आत्मनिर्भरता के संकल्प से रोजगार बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को गति देने का दोहरा उद्देश्य पूरा हो सकता है। मगर सबसे बड़ी बात यह कि दोतरफा सीमा तनाव के मौजूदा माहौल ने राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर जो अतिरिक्त चिंताएं पैदा की हैं, उनका सबसे अच्छा जवाब सैन्य जरूरतों के मामले में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता से ही दिया जा सकता है।

जब तक स्वार्थी नेताओं को नहीं हटाएंगे किसान तब तक नहीं निकल सकता मुद्दे का हल

केंद्र सरकार तथा आंदोलनकारी किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ता के बाद भी दोनों पक्षों को स्वीकार्य कोई हल अब तक निकल नहीं सका है। वस्तुतः संपूर्ण घटनाक्रम शाहीन बाग की याद दिला रहा है। जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर चंद मुट्ठी भर अमीर से बेहद अमीर किसानों के नेतृत्व में पंजाब तथा हरियाणा के बहुसंख्य किसानों ने न केवल दिल्ली बल्कि आसपास के चतुर्दिक सामान्य जनजीवन को अस्त–व्यस्त कर दिया है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रदर्शनकारी या तथाकथित अन्नदाता किसान दिल्ली के समीप सिंघु बॉर्डर पर पिछले पचास दिनों से डेरा डाले बैठे हुए हैं जिससे सामान्य किसानों की रोजी–रोटी पर तो कुठाराघात हो ही रहा है, साथ ही दैनिक मजदूरों और अन्य दिहाड़ी कामगारों को भी अपने जीवकोपार्जन में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वस्तुतः उनके इस अनवरत प्रदर्शन से दिल्ली तथा संबंधित सभी राज्यों की कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस तथा प्रशासनिक मशीनरी को इन अन्नदाताओं के धरना स्थलों की सुरक्षा तथा दिल्ली के चारों ओर सभी राज्यों से यहाँ प्रतिदिन आकर काम करने वालों के लिये दैनिक आवागमन सुलभ बनाने तथा सामान्य कानून एवं व्यवस्था की स्थापना करने में भी एड़ी–चोटी एक करनी पड़ रही है। इसमें न केवल देश के करदाताओं का अमूल्य धन नष्ट हो रहा है जिसका अन्यथा सामाजिक कल्याण एवं विकास के कार्यों में उपयोग किया जा सकता था बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले का परिश्रम नष्ट हो रहा है जिससे निश्चय ही सामान्य जनजीवन की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती थी तथा उनका राष्ट्रहित में उपयोग किया जा सकता था।

यद्यपि ये अन्नदाता कृषि कानून को वापस लिये जाने पर अड़े हैं तथा इसके लिए केंद्र सरकार पर अनेकों प्रकार से दबाव बना रहे हैं जिसमें देश के कुछ प्रमुख तथाकथित बुद्धिजावियों के साथ लगभग सभी प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल और चीन समर्थित माओवादी कम्युनिस्ट पार्टियां तथा लंदन से खालिस्तान समर्थक उग्रवादी संगठन भी भरपूर समर्थन दे रहे हैं जो अखंड भारत के भीतर एक स्वतंत्र पंजाबद खालिस्तान देश का सपना संजोए बैठे हैं। निश्चय ही इन अन्नदाताओं ने अपने निहित स्वार्थों के लिए संपूर्ण देश के बहुसंख्यक सामान्य किसानों को बुरी तरह से भ्रमित करके डरा दिया है क्योंकि इनके लिए राष्ट्रहित का कोई महत्व नहीं है, अन्यथा किसानों के आंदोलन में इन सभी विघटनकारी तत्वों का क्या काम है। यद्यपि कृषि कानून में उल्लिखित विभिन्न सकारात्मक प्रावधानों के महत्व को ये अन्नदाता मौन रूप से स्वीकार कर रहे हैं तथापि अपने संकीर्ण स्वार्थों की निर्बाध पूर्ति के लिए ये इन सभी महत्वपूर्ण किसान–हितकारी उपबंधों की उपेक्षा कर रहे हैं जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम0एस0पी0) की गारंटी के साथ ही किसानों को अपनी फसल को देश के किसी भी स्थान पर बेचे जाने की छूट दी गयी है तथा मंडियों में फैले भ्रष्टाचार से उन्हें बचाने का प्रयास भी किया गया है। संभवतः अपने इन तुच्छ स्वार्थों एवं संकीर्ण उद्देश्यों के चलते तथा इस आंदोलन के देश विरोधी और विघटनकारी–आतंकवादी तत्वों के हाथों में पड़ जाने के कारण इन आंदोलनकारी किसान नेताओं में उत्पन्न निराशा साफ दिखायी दे रही है।

वास्तव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे संपूर्ण विश्व अचंभित है परंतु देश के भीतर तथा विदेश में बैठे इन कट्टर राष्ट्रविरोधी ताकतों को अच्छा नहीं लग रहा है। विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष यथा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन तथा आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आदि सभी प्रमुख नेतागण प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से अत्यंत प्रभावित हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी की विश्व में बढ़ती हुई लोकप्रियता की स्वीकारोक्ति ही है कि अनेक प्रमुख देश उन्हें अपने–अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं।

वर्तमान कोरोना की विश्वव्यापी महामारी के दौर में देश के प्रधानमंत्री ने जिस सूझ–बूझ का परिचय देते हुए सभी देशवासियों की सुरक्षा एवं उनके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सारे व्यापक उपाय किए उसकी न केवल देश में बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी वैश्विक संस्था तथा विभिन्न देशों द्वारा कई प्रमुख मंचों पर भूरि–भूरि प्रशंसा की गई। कोविड–19 के कठिन दौर में भी जब पड़ोसी देश चीन ने अत्यंत शर्मनाक विश्वासघात करते हुए भारत–चीन सीमा, (एल0ए0सी0) पर देश में अनेक स्थानों पर घुसपैठ करने की कोशिश की, उसका अत्यंत साहसपूर्वक ढंग से सामना करते हुए भारतीय सेना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजिंग को जिस तरह से मुँहतोड़ जवाब दे रही है उससे चीन बेहद परेशान हो चुका है तथा उसके कारण चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न केवल विश्व में बल्कि अपने देश में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। समग्रतः विश्व में भारत की तेजी से उभरती सशक्त छवि देशविरोधी शक्तियों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन चुकी है। अतः ये सब, जिनमें देश के भीतर सक्रिय टुकडे–टुकड़े गैंग की प्रभावी भूमिका रहती है, केवल मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे भारत को एक बार पुनः अस्थिर तथा विखंडित किया जाए। किसानों के इस आंदोलन ने इन्हें पुनः एक मौका दे दिया है।

ऐसे चिंताजनक परिदृश्य में यद्यपि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस कानून पर रोक लगा कर केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच चले आ रहे लंबे टकराव पर विराम लगाने का प्रयास तो किया है और समाधान निकालने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है परंतु एक सदस्य द्वारा समिति में शामिल न होने के फैसले से आगे की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है और विलंब हो सकता है। इसी असमंजस के बीच इन आंदोलनकारी किसानों द्वारा देश के आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर विशाल ट्रैक्टर जुलूस निकालने की चेतावनी दोनों पक्षों के बीच तनाव को बढ़ाने का काम करेगी। अंततोगत्वा सरकार तथा आंदोलनकारी किसानों को ही इस समस्या का हल खोजना होगा जो दोनों के बीच बातचीत से ही निकल सकता है। लेकिन इसके लिए इन किसान आंदोलनकारियों को अपने बीच से स्वार्थी किस्म के छद्म नेताओं तथा विघटनकारी तत्वों को हटाना होगा क्योंकि तभी दोनों के बीच सार्थक वार्तालाप हो सकेगा और दोनों पक्षों को स्वीकार्य हल निकल सकेगा, जो अब तक की कई दौर की वार्ता के सम्पन्न होने पर भी नहीं निकल सका। साथ ही देश के संपूर्ण जनता–जर्नादन अर्थात् हम भारत के लोग को भी जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, क्षेत्र आदि जैसे संकीर्ण विचारों से ऊपर उठना चाहिए तथा किसान आंदोलन के नाम पर अपने तुच्छ हितों की रक्षा करने वाले इन स्वार्थी और देश विरोधी किसान नेताओं एवं असामाजिक तत्वों तथा कट्टर राष्ट्रविरोधी–विघटनकारी एवं खालिस्तान समर्थक उग्रवादी संगठनों को अलग–थलग कर देना चाहिए जिससे देश की अखंडता तथा राष्ट्रहित और मानव संस्कृति की रक्षा हो सके तथा समाज में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के साथ ही सामाजिक समरसता भी कायम की जा सके। ऐसा हो सकता है क्योंकि मानव उद्यम से परे कुछ नहीं होता है।

नरम से गरम हुए सुशासन बाबू, क्यों बदले–बदले से सरकार नजर आते हैं...

32 दांतो के बीच में जीभ कैसे रहती होगी। ये बहुत पुरानी कहावत है। जब इंसान बेबसी में काम करता है तो ऐसी कई मिसालें दी जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री, पीएम मैटेरियल वाले मुख्यमंत्री, सुशासन बाबू के उपनाम वाले मुख्यमंत्री, बिहार में बहार हो का नारा देने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री। नाम– नीतीश कुमार। इन दिनों पहचान एंग्री मैन के रूप में हो रही है। सुशासन बाबू को शायद ही इससे पहले इतने गुस्से में देखा गया हो। लेकिन बीते कुछ महीने से चाहे वो चुनावी रैलियों की बात हो या पत्रकारों के सवाल नीतीश बात–बात पर भड़क जाते हैं। कमियों को दूर करने की बजाए सवाल पूछने वालों को ही पार्टी विशेष का समर्थक करार दे देते हैं। डीजीपी को सबके सामने फोन पर फटकार लगाते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर फूट पड़ते हैं। इस बार छोटे भाई की भूमिका में आए नीतीश के तेवर पिछले कुछ वक्त से ही बदले–बदले नजर आ रहे हैं।

अक्सर भाषण देते हुए अपनी बात शांति से रखने वाले नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक खासियत यही मानी जाती थी कि वो बेहद ही नपा–तुला बोलते थे। कड़वी से कड़वी बात भी मुस्कुराते हुए इस अंदाज में बोल जाते कि विरोधी भी यह समझ नहीं पाते कि आखिर नीतीश पर निशाना साधे तो साधे कैसे? याद कीजिए 2015 का चुनाव जब एनडीए से बाहर होकर चुनाव मैदान में उतरी जेडीयू के सामने भव्य आभा कौशल वाले नरेंद्र मोदी खड़े थे। नरेंद्र मोदी उस चुनाव में नीतीश कुमार पर हमलावर रहते। लेकिन पीएम की रैली के बाद नीतीश बेहद ही सौम्यता के साथ एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तर्कों और तथ्यों के साथ उनकी कही हर बात को काटते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से लोग एक अलग ही नीतीश कुमार को देख रहे हैं। जो बात–बात पर अपना आपा खो रहे हैं। कमियों को दूर करने की बजाये सवाल पूछने वालों पर ही सवाल उठाने लग रहे हैं। सुशासन बाबू को इतने ही गुस्से में तब देखा गया था जब वो रैलियां कर रहे थे। उस वक्त का तनाव तो समझ में आ रहा था कि डर था कि चुनाव में जीत होगी या नहीं। लेकिन अब सत्ता मिल गई। फिर आखिर क्यों नीतीश बात–बात पर इतना गुस्सा हो रहे हैं। ये सवाल बिहार से लेकर दिल्ली तक पूछा जा रहा है।

कभी उन्हें इसकी आदत नहीं रही। साल 2005 से वो मुख्यमंत्री रहें वो और जो भी फैसले किए अपनी मर्जी से अपने दम पर किया। चाहे वो सीएम पद छोड़ जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना हो या बीजेपी के लिए डिनर कैंसिल करना। लालू का साथ छोड़ बीजेपी के साथ आ जाना जो भी फैसला करते पूरे दमखम के साथ करते।

नीतीश सुलझे हुए मुख्यमंत्री माने जाते रहे हैं और गुड गवर्नेंस के मामले में उनकी सानी नहीं रही है तभी तो एक वक्त ऐसा भी था जब प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए में नीतीश के नहीं होने के बावजूद उनके गुड गवर्नेंस की तारीफ की थी। जिस ला एंड ऑर्डर को लेकर घर के अंदर और बाहर नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहे हैं। चाहे वो एनडीए हो या विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर उनपर सवाल उठ रहे हैं

बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ा और जनता दल यूनाइटेड के कम सीटों पर जीत हासिल करने के बावजूद भाजपा ने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोंकने की बजाय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनाई। । आज नीतीश 43 विधायकों वाली छोटी पार्टी के अगुवा हैं। उनसे ज्यादा विधायक 74 सीटों की संख्या बीजेपी के पास है। यानी कि जो बड़ा भाई हुआ करता था वो अचानक से छोटा भाई

हो गया। वो झुंझलाहट है मन में। इसके साथ ही बीजेपी के विरोध के आगे विवश होकर नीतीश को 15 साल से गृह सचिव रहे आमिर सुबहानी को हटाना पड़ा।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू सहयोगी भाजपा से छोटी पार्टी बन गई है। दूसरे, भाजपा की आंतरिक संरचना भी बदल गई है। सीएम नीतीश के साथ आदर्श और भरोसेमंद सहयोगी की भूमिका निभाने वाले सुशील मोदी को भाजपा ने राज्यसभा सदस्य बनाकर दिल्ली भेज दिया है। उनकी जगह दो उप–मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश की गई है। हालत यह हो गई है कि अब नीतीश कुमार को भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ डील करना पड़ रहा है। राज्य में भाजपा अब बिग बॉस की भूमिका में आना चाहती है लेकिन नीतीश उसे बिग बॉस मानने को तैयार नहीं और इसलिए छोटे दल के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही नीतीश लगातार अपना कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जार्ज फर्नांडीज को हटाकर शरद यादव को जेडीयू का अध्यक्ष बनवा दिया था। फिर ठीक पांच साल पहले नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष पद शरद यादव से जबरन हासिल किया था। वहीं नीतीश कुमार कहते सुनाई पड़े की पार्टी का कामकाज किसी फुल टाइम अध्यक्ष के हाथों में होनी चाहिए। नीतीश ने इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बना दिया। दरअसल, नीतीश के पास अब कोई रास्ता नहीं था कि वो पार्टी से ऐसा कोई नुमाइंदा चुने जो बीजेपी के नेताओं से बात करे। कहा तो ये भा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भूपेंद्र यादव से बात करने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। नीतीश को ऐसे किसी शख्स की दरकार थी तो अधिकृत तौर पर बीजेपी से बात कर सके। नीतीश को बार–बार भूपेंद्र यादव या बीजेपी की दूसरी–तीसरी कतार के नेताओं से बात करने

नीतीश कुमार की एक खासियत और रही है कि वो मीडिया से बहुत कम बात करते रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर विधानसभा तक, पत्रकार सवालों की झड़ी लगाते नजर आते थे लेकिन नीतीश मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर निकल जाया करते थे। लेकिन इस बार तो पटना का हर पत्रकार नीतीश कुमार के रवैये से काफी हैरत में नजर आ रहा है। पत्रकार जब भी कोई सवाल लेकर नीतीश का नाम लेते हैं तो नीतीश कुमार खुद ही रुक कर जवाब देना शुरू कर देते हैं। बीच में तो कई दिन ऐसे भी गुजरे जब दिनभर में नीतीश कुमार ने 4–5 बार पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। साफ–साफ लग रहा है कि अपनी चुप्पी त्यागकर नीतीश खूब घूम रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं और हर सवाल का जवाब दे रहे हैं।

नीतीश कुमार खुद को मजबूत करने की भी कवायद में लगे हैं। कभी वो मांझी को साथ लाते हैं। फिर रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा से नजदीकियां बढ़ाते हैं। यहां तक की रालोसपा और हम के जेडीयू में विलय की खबरें भी सामने आती है। कुल मिलाकर कहा जाए कि नीतीश बहुत दवाब में हैं। बिहार के नतीजों से नाखुश हैं। अपनों और विरोधियों के हमले से चितिंत हैं। लेकिन नीतीश को अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के महान नेता, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों श्क्ष्या हार में क्ष्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सहीश्श को पढ़ते हुए अपने रास्ते में आगे बढ़ना होगा। नीतीश सोलह साल से मुख्यमंत्री हैं तो चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो या फिर बढ़ते अपराध की, सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। इसमें झुंझलाना और बिफरना सेहत के लिए भी खराब है और कुर्सी के लिए भी। – अभिनय आकाश

गाँव–गाँव में पार्टी की मजबूती के लिए भाजपा ने बनाया मेगा प्लान

भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 1980 में गठन के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में दो सीटें जीतने वाली बीजेपी के आज तीन सौ से अधिक सांसद हैं। कई राज्यों

में उसकी सरकारें हैं, लेकिन बीजेपी आज भी सर्वमान्य पार्टी नहीं बन पाई है। दक्षिण के राज्यों में उसकी पकड़ नहीं के बराबर है। कर्नाटक को छोड़ दें तो दक्षिण के राज्यों– आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में आज भी बीजेपी ज्यादातर मुकाबले में नजर नहीं आती है। इसी के चलते बीजेपी पर पूरे देश की बजाए उत्तर भारतीयों की पार्टी होने का ठप्पा चस्पा रहता है। उत्तर भारत में भी बीजेपी को लेकर बुद्धिजीवियों और राजनैतिक पंडितों की अलग–अलग धारणा है। कभी बीजेपी को बनिया (व्यापारियों) और ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था, तो ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं थी जो बीजेपी को शहरी पार्टी बताया करते थे। इस अभिशाप को मिटाने के लिए बीजेपी को काफी पापड़ बेलने पड़े तो प्रभु राम ने उसका (बीजेपी) बेड़ा पार किया।

अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली के पांच सौ वर्ष पुराने विवाद में 'कूद' कर बीजेपी ने ऐसा रामनामी चोला ओढ़ा कि वह बनिया–ब्राह्मण की जगह हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद की लम्बरदार बन बैठी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) की राजनैतिक इकाई भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से अलग–अलग अपनी ढपली बजाने वाले हिन्दुओं को भगवान राम के नाम पर एकजुट करके उसे बीजेपी का वोट बैंक भी बना दिया, लेकिन फिर भी बीजेपी के ऊपर शहरी पार्टी होने का ठप्पा तो लगा ही रहा। यह वह दौर था जब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस सहित अन्य तमाम गैर–भाजपाई दल मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत में लगे हुए थे। वहीं हिन्दुओं के वोट बंटे रहें, इसके लिए साजिशन हिन्दुओं के बीच जातिवाद घोलकर उनके वोटों में बिखराव पैदा किया गया। यादवों के रहनुमा मुलायम बन गए और मायावती दलितों को साधने में सफल रहीं। हिन्दुओं के वोट बैंक में बिखराव के सहारे ही बिहार में लालू यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने वर्षों तक सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल की। बसपा सुप्रीम मायावती ने भी कई बार दलित–मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में कामयाबी हासिल की। यह सब तब तक चलता रहा जब तक कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी युग का श्रीगणेश नहीं हुआ था।

2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद की ऐसी अलख जलाई की शहर से लेकर गाँव तक में मोदी–मोदी होने लगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि बीजेपी ने गाँव–देहात में अपने संगठन को मजबूत कर लिया था। बीजेपी पर शहरी पार्टी होने का ठप्पा लगा था। इस ठप्पे को हटाने के लिए ही मोदी सरकार ने तमाम विकास योजनाओं का रूख गांव–देहात और अन्नदाताओं की तरफ मोड़ दिया। फसल बीमा योजना, कृषि में मशीनीकरण, जैविक खेती, सॉइल हेल्थ कार्ड और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। किसानों से लगातार संवाद किया जा रहा है। किसानों की माली हालत सुधारने के लिए कई राहत पैकजों की भी घोषणा की गई। नया कृषि कानून भी इसका हिस्सा है जिसको लेकर आजकल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल रखा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नये कृषि कानून पर अंतरिम रोक लगा कर एक कमेटी भी गठित कर दी है।

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किसानों को लेकर कई कदम उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी केन्द्र सरकार के पदचिन्हों पर चलते हुए कई किसान योजनाएं लेकर आई है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में सिंचन क्षमता में वृद्धि तथा सिंचाई लागत में कमी लाकर कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 50 लाख किसान ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई योजना से लाभान्वित हुए। योजना में लघु एवं सीमांत कृषकों को 90 प्रतिशत एवं सामान्य कृषकों को 80 फीसदी का अनुदान मिला है। लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक समूह के लिए मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना की भी शुरूआत की गई है। योजना के तहत नलकूप के सबमर्सिबल पम्प का संचालन सौर ऊर्जा के माध्यम से किया जाएगा।

योगी सरकार खेतों की मुफ्त में जुताई और बुवाई का भी कार्यक्रम लेकर आई है। पहले चरण में ये योजना यूपी के लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर समेत 16 जिलों में लागू की गई। इसके तहत लघु और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने ट्रैक्टरों से मुफ्त में खेतों की जुताई और बुवाई कराने जैसी बड़ी सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री कृषक योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाल ही में किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.13 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 28,443 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये। देश के किसानों के लिए यह सब योजनाएं केन्द्र की मोदी सरकार लाई है तो यूपी की योगी सरकार अपने प्रदेश के किसानों की माली हालत सुधारने में लगी है।

बात सरकार से अलग संगठन की कि जाए तो भारतीय जनता पार्टी इसमें भी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है। शहर के चौक–चौराहों से निकलकर बीजेपी गाँव–देहात में चौपालों तक दस्तक देने लगी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनावों में भी ताल ठोंकने लगी है। कई राज्यों के पंचायत चुनाव में बीजेपी अपनी ताकत दिखा भी चुकी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने गांव की सरकार के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा पंचायत चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। अबकी बार बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह कमल के निशान पर पंचायत चुनाव लड़ने जा रही है ताकि भविष्य में बीजेपी ताल ठोक कर कह सके कि उसकी पहुंच गाँव–गाँव तक है।

दरअसल, पार्टी अभी तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत) में अपने उम्मीदवारों को सिर्फ समर्थन देती थी, सिंबल नहीं दिया जाता था। प्रत्याशी को बीजेपी समर्थित कहा जाता था, लेकिन मौजूदा बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि हर राजनीतिक दल को खुद का कर्तव्य मानकर हर चुनाव में उम्मीदवार उतारने चाहिए क्योंकि चुनाव के दौरान सियासी दलों को अपनी नीतियां और योजनाओं को आमजन के सामने रखने का खास अवसर मिलता है। चुनाव सियासी दलों की परीक्षा समान हैं।

जुलाई में नहीं अब 16 जून को ही खुल जाएंगे परिषदीय विद्यालय

सुलतानपुर सं0। कोरोना संक्रमण के चलते आगामी नए सत्र से परिषदीय विद्यालयों में होने वाली छुट्टियों में कटौती कर दी गई है। अब छात्र ग्रीष्मकालीन छुट्टी का 21 मई से 15 जून तक ही मजा ले सकेंगे। ऐसे में एक जुलाई को खुलने वाले विद्यालयों को 16 जून को ही खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है।

जिले में वर्तमान में 2064 परिषदीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं, इनमें 1450 प्राथमिक, 344 उच्च व 270 कंपोजिट विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में पंजीकृत दो लाख 32 हजार छात्रों के लिए पठन–पाठन कार्य संपन्न कराया जा रहा है। सालाना परीक्षा के बाद 21 मई से 31 जून तक गर्मी की छुट्टी कर दी जाती है। अब 40 दिन की छुट्टी की जगह 25 दिन की ही गर्मी की छुट्टी की जाएगी।

शासन की तरफ से जारी किए गए कैलेंडर में होलिका दहन व होली की छुट्टी 28 और 29 मार्च को निर्धारित की गई है। 26 जनवरी, 15 अगस्त व गांधी जयंती दो अक्टूबर को पूर्व की तरह स्कूल तो खुलेंगे, लेकिन अध्यापन कार्य नहीं किया जाएगा। 27 फरवरी को संत रविदास व 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती पर छुट्टी नहीं की जाएगी। वहीं, 25 अप्रैल को महावीर जयंती, 22 अगस्त रक्षाबंधन व सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती रविवार को पड़ रही है। इसी क्रम में 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर सिंह शहीद दिवस की एक नई छुट्टी कैलेंडर में शामिल की गई है।

कैलेंडर में स्कूलों के खुलने व बंद होने का समय भी तय कर दिया गया है। इसके तहत एक अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह आठ से दो बजे तक स्कूल खोले जाएंगे। एक अक्तूबर से 31 मार्च तक सुबह नौ से तीन बजे तक स्कूल का संचालन होगा। गर्मी में साढ़े दस से 11 बजे व सर्दियों में दोपहर 12 से साढ़े 12 बजे तक मध्यावकाश किया जाना निर्धारित किया गया है। एबीएसए केके सिंह ने बताया कि शासन की तरफ से जारी कैलेंडर के अनुसार स्कूलों का संचालन किया जाता है। इस बार समय अधिक मिलने से पठन–पाठन को बेहतर किया जा सकेगा।

उपभोक्ताओं को सौंपी जाएगी नहर निगरानी की जिम्मेदारी

सुलतानपुर सं0। पटरियों की कटान रोकने, टेल तक पानी पहुंचने की निगरानी के साथ सभी किसानों को सिचाई का मौका मिल सके इसके लिए विभाग ने कार्ययोजना तैयार की है।

जिले के सभी नहर खंडों पर अब जल उपभोक्ता समितियों का गठन किया जाएगा। सिर्फ खंड 49 में ही गठित उपभोक्ता समिति निष्क्रिय है। वित्तीय वर्ष से पूर्व समितियों के गठन की तैयारी है।

जिले में नहरों का विस्तृत संजाल है। शारदा सहायक के चार खंडो के जरिए 1096 किमी लंबाई मे विस्तृत नहरों के जरिए यहां के कुल कृषि क्षेत्र का 45 फीसद क्षेत्रफल नहरों के पानी से सिचाई पर आश्रित है। ऐसे में यहां की खेती के लिए नहरें अन्नदाताओं के लिए जीवन रेखा जैसी हैं। इन नहरों की विफलता और इनका सुचारू संचालन किसानों के लिए संकट बन जाता हैं। पांच नहर खंडों में जिले के मध्य गुजरी गोमती नदी के समानांतर उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में शारदा सहायक नहरों की तीन दशक पुरानी नहर प्रणाली ध्वस्त होने की कगार पर है। ऐसे में विभाग ने नहर की सिचाई व्यवस्था से आम किसानों को जोड़ने के लिए हर नहर प्रणाली पर जल उपभोक्ता समिति के गठन की तैयारी की है।

किसानों को मिलेगा सिर्चाई का अधिकार रू नहरों से सिचाई की समस्या से जूझ रहे किसान अब भी विश्व बैंक से पोषित उस योजना के लाभ से वंचित हैं, जिसके तहत किसानों को नहरों पर उन्हें स्वामित्व मिलना है। वाटर सेक्टर रिस्ट्रेक्चर प्रोजेक्ट (डब्लूएसआरपी) नामक इस पायलट योजना की शुरुआत के एक दशक बीत जाने के बाद भी इस पर जिले में कोई अमल नहीं हुआ है।

चार साल में ही ढह गया बरुई अंत्येष्ठि स्थल का टिनशेड

सुलतानपुर सं0। गोमती नदी किनारे बरुई गांव में शमशान स्थल का टिनशेड चार साल में ही ढह गया। घटिया निर्माण के चलते यह ढांचा अधिक वक्त तक नहीं टिक सका। यहां का शौचालय भी बदहाल हो गया है। आने जाने का रास्ता भी ठीक नहीं है। जिससे लोगों को परेशानी होती है।

गाजियाबाद के मुरादनगर के बने अंत्येष्ठि स्थल का हादसा देखकर भदैंया के गोमती नदी किनारे बने बरुई के शवदाह स्थल की याद ताजा हो जाती है। जिसका भवन बनने के बाद से ही जर्जर है तथा शौचालय उखड़कर बदहाल हो गया है। पांच साल पहले गोमती नदी किनारे बरुई घाट के बगल करीब बीस लाख की लागत से श्मशान घाट अंत्येष्ठि स्थल का निर्माण कराया गया है। इसके शुरुआत मे ही घटिया निर्माण का आरोप लगा फिर भी काम पूरा कर भुगतान हो गया। इस स्थल पर बने कक्ष की फर्श बनने के साल भर के भीतर ही धंस गई है। कमरे के ऊपर का टिनशेड भी टूटकर गिर गया है। इससे गर्मी में धूप व बारिश में पानी कमरे में पहुंचता है। पांच साल पहले बने श्मशान घाट पर बने कक्ष की दीवारों में दरार आ गई है तथा कक्ष का दरवाजा कोई उखाड़ ले गया है। घटिया निर्माण के चलते माघ की ठंड व जून की गर्मी में भी लोग बने कक्ष के नीचे गिरने के भय से नहीं बैठते हैं। अमूमन शव के दाह संस्कार मे तीन से चार घंटे लगते हैं लेकिन लोग पेड़ों के नीचे ही समय बिताकर काम चलाते हैं। यूं तो यहां सात शौचालय बने हैं लेकिन सब के सब जर्जर हो गए हैं। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी राममिलन वर्मा ने बताया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जांच पड़ताल करा व्यवस्था ठीक कराई जाएगी।

तीन केंद्रों पर 71 फीसद लाभार्थियों को लगी एंटी कोरोना वैक्सीन

सुलतानपुर सं0। जिला महिला अस्पताल, सीएचसी अखंडनगर और बल्दीराय समेत तीन केंद्रों पर शनिवार से कोरोना के पहले चरण का टीकाकरण शुरू कर दिया गया। इस बहु प्रतीक्षित टीके की शुरुआत को एतिहासिक बनाने के लिए केंद्रों को रंगोली व रंग–बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। टीका लगवाने वाले कुछ चुनिदा कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया गया। जिला महिला अस्पताल में आर्थो सर्जन डॉ. पीके राय को जिले का पहला टीका सुबह दस बजकर 45 मिनट पर लगाया गया। वहीं, महिला अस्पताल के गायनी सर्जन डॉ. आनंद सिंह व सीएचसी अखंडनगर के प्रभारी डॉ. रमेश यादव को पूर्वाह्न 11 बजे टीका लगवाने वाले दूसरे नंबर के लाभार्थी बने। इन केंद्रों पर पंजीकृत किए गए लाभार्थियों में से करीब 29 फीसद लोग वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचे।

जिला महिला अस्पताल में पंजीकृत कुल 100 में से 74 लोगों को टीका लगाया गया। टीकाकरण के दौरान एक एएनएम की तबीयत खराब हो गई। सूचना पर सीएमएस डॉ. एससी कौशल समेत अन्य जिम्मेदार पहुंच गए। स्वास्थ्य जांच के दौरान पाया गया कि महिला स्वास्थ्य कर्मी हाईपरटेंशन की मरीज थीं, जिन्हें ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। अखंडनगर केंद्र पर टीकाकरण के लिए 45 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां और 55 स्वास्थ्य कर्मी समेत कोविन पोर्टल पर पंजीकृत 100 में से पहुंचने वाले 68 लोगों को टीका लगाया गया। दिलचस्प बात यह है कि टीका लगवाने वालों में 65 महिलाएं व तीन पुरुष लाभार्थी शामिल रहे।

वहीं, टीकाकरण की वजह से चक्कर आने से असहज महसूस कर रही एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री की जांच स्वयं चिकित्सा प्रभारी डॉ. रमेश यादव द्वारा की गई। पाया गया कि महिला ब्लड प्रेशर की मरीज हैं और उन्होंने दवा भी नहीं खाई थी। टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव उद्बोधन को देखने व सुनने के लिए प्रतीक्षा कक्ष एलईडी की भी व्यवस्था की गई थी।

बल्दीराय में स्थानीय सीएचसी पर पंजीकृत 100 में से 79 लोग टीका लगवाने के लिए केंद्र पर पहुंचे थे। चिकित्साधिकारी डॉ. राजेश कुमार की अगुवाई की गई स्वास्थ्य जांच में अस्वस्थ पाए जाने पर पांच लाभार्थियों को टीका नहीं लगाया गया। बच्चे को स्तनपान कराने के चलते भी दो महिलाओं का टीकाकरण नहीं किया गया। यहां नदरई गांव निवासी आशा बहू बिदू सिंह को पहला टीका लगाया गया। एसडीएम राजेश सिंह ने टीका लगवाने वाले शुरुआती पांच कोरोना योद्धाओं को शाल देकर सम्मानित किया।

टीका लगवाकर, दिया संदेश :

जिला महिला अस्पताल में पहला टीका लगवाने वाले डॉ. पीके राय ने कहा कि हमारे वरिष्ठ विज्ञानियों ने काफी रिसर्च के बाद टीका तैयार किया है। टीकाकरण का पहला लाभार्थी होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वहीं, 13 हजार लाभार्थियों में पहले नंबर पर पंजीकरण कराने वाले अखंडनगर सीएचसी प्रभारी डॉ. रमेश यादव ने कहा कि टीकाकरण से कोई समस्या नहीं होती है, इसके लगने से हम कोरोना को मात देने में सफल होंगे। भ्रांतियों को दरकिनार कर इसमें बढ़–चढ़कर हिस्सा लेने की भी उन्होंने लोगों से अपील की। डॉ. आनंद सिंह, डॉ. ओम प्रकाश पांडेय, गीता देवी व अंजली गुप्ता ने कहा कि शरीर में एंटी बॉडी के विकास के लिए टीका लगवाना बेहद जरूरी है।

भ्रमण कर निर्देश देते रहे जिम्मेदार :

टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए डीएम रवीश गुप्ता, सीडीओ अतुल वत्स, सीएमओ डॉ. डीके त्रिपाठी, डॉ. राम आसरे, डॉ. लालजी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. एएन राय, जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. एससी कौशल, एसडीएम राजेश सिंह, महेंद्र कुमार, सीओ सतीश चंद्र शुक्ल, सुरेंद्र कुमार समेत उच्चाधिकारी केंद्रों का दौरा करते रहे। निरीक्षण के दौरान कोई कमी नहीं पाई गई, फिर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

पूरा होगा निर्धनों के आशियाने का सपना

सुलतानपुर सं0। कहीं नीव भरकर तो कहीं छत के बिना निर्धनों के आवास छह माह से अधूरे थे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के एक साल पहले आए आदेश में यह कहा गया कि नदी के बाढ़ क्षेत्र को दो सौ मीटर तक पूरी तरह खाली करा दिया जाए। ऐसे में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लाभार्थी दोहरे संकट में आ गए।

आवास तो अधूरा रह ही गया, साथ ही उन्हें उनकी जमीनों से विस्थापित किए जाने की तैयारी भी की जाने लगी। एक माह पूर्व एनजीटी की ओर से इस दायरे को घटा कर 50 मीटर किए जाने से संकट में आए साधन विहीन लोगों को अब संजीवनी मिल गई। आशियाना पाने की उम्मीद पर छाए संशय के बादल छंट गए हैं। नए आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग की टीम ने जांच पूरी कर ली है। अधिकतर आवेदक अब इस दायरे से बाहर हैं। आवेदकों को आवास के लिए दूसरी किस्त जारी की जा रही रही है।

परियोजना अधिकारी डूडा सुनीता सिंह ने बताया कि नए आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग की टीम ने जांच पूरी कर ली है। ज्यादातर आवेदक अब इस दायरे से बाहर हैं। विभाग इनके आवास निर्माण के लिए शीघ्र ही अवशेष किस्तें जारी कर देगा।

निर्धनों में जागी उम्मीद रू

तट क्षेत्र का दायरा कम किए जाने से आवेदकों को राहत मिली है। प्रधानमंत्री शहरी आवास के तहत पहले प्रभावित 36 आवेदकों में से अब सिर्फ आठ इस दायरे में में आ रहे हैं। नदी तट के किनारे आबाद नगर पालिका के कई वार्ड में जांच पड़ताल के बाद जिला नगरीय विकास अभिकरण(डूडा) की ओर से इन आवेदकों को आवास की किस्तें दी जा रही है। अब निर्धनों को आवास पूरा होने की उम्मीद है।

अब पोर्टल पर दर्ज होगी परिषदीय विद्यालयों की गोपनीय रिपोर्ट

सुलतानपुर सं0। अब परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षकों की मैनुअल तैयार की जाने वाली वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिसमें अध्यापकों को ऑपरेशन कायाकल्प, स्वंय के साथ छात्र–छात्राओं की उपस्थिति व रिजल्ट के परिणाम प्रतिशत पर अंक दिए जाएंगे।

साल भर में मिले अंकों का औसत मूल्यांकन कर खंड शिक्षाधिकारियों द्वारा सालाना रिपोर्ट तैयार कर बीएसए के पास भेज दी जाएगी। जिसके आधार पर में बेहतर अंक पाने वाले शिक्षक पदोन्नति व वेतन वृद्धि की राह आसान की जाएगी।

जिले में चल रहे 2064 परिषदीय स्कूलों में 1450 प्राथमिक, 344 उच्च व 270 कंपोजिट विद्यालय शामिल हैं। इसमें कुल आठ हजार शिक्षकों द्वारा पंजीकृत दो लाख 32 हजार छात्रों को अध्यापन कार्य संपन्न कराया जा रहा है। बेसिक स्कूलों के पठन–पाठन से लेकर सभी गतिविधियों को ऑनलाइन किया जा रहा है। शिक्षकों की हाजिरी से लेकर छात्रों के नामांकन आदि के लिए भी रजिस्टर के इस्तेमाल से परहेज किए जाने की कवायद चल रही है। शासन की तरफ से अब शिक्षक–शिक्षिकाओं की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को भी अब मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किए जाने की बात कही गई है। तैयार होने वाली गोपनीय रिपोर्ट में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के 14 बिंदु पूरे होने पर शिक्षकों को अधिकतम दस अंक दिए जाएंगे। लर्निंग आउटकम परीक्षा में ए–प्लस ग्रेड मिलने पर अधिकतम 20 अंक मिलेंगे। दीक्षा पोर्टल के नियमित उपयोग व समय पर रिजल्ट कार्ड उपलब्ध कराने पर भी दस–दस अंक दिया जाना निर्धारित किया गया है। विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) की नियमित बैठक और विद्यार्थियों की ओर से पुस्तकालय के नियमित प्रयोग पर भी अंक दिए जाएंगे। इन सभी बिंदुओं पर औसत निकालकर संस्तुति के लिए ऑनलाइन रिपोर्ट बीएसए के पास भेज दिया जाएगा। एबीएसए केके सिंह ने बताया कि शिक्षकों का मूल्यांकन पहले भी किया जाता था, लेकिन मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन फीडिग से इसमें पारदर्शिता आएगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, सरिता मिश्रा के लिए एस0 पी0 प्रिटिंग प्रेस धनपतगंज सुलतानपुर उ0प्र0 से मुद्रित तथा 1180 सिविल लाइन गोलाघाट सुलतानपुर उ0प्र0 से प्रकाशित ।

सम्पादक–

जितेन्द्र मिश्र

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र सुलतानपुर जनपद होगा ।

e-mail id

missionvijaynews@gmaill.com